Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPPM13

दृष्टि The Vision

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

MPPCS DLP

विषय सूची (Contents)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय **5-19**

1.1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था 5

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था : प्रकृति, विशेषताएँ, वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ 7

1.3 उत्पादन के कारक एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 11

1.4 कुछ महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट 13

2. आर्थिक विकास, आर्थिक संवृद्धि एवं अल्प विकास **20-39**

2.1 आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि 20

2.2 आर्थिक विकास के मापन 21

2.3 सामाजिक-आर्थिक लेखांकन 25

2.4 आर्थिक विकास की रणनीति 29

2.5 आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 31

3. राष्ट्रीय आय **40-51**

3.1 राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा 40

3.2 राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ 41

3.3 जी.डी.पी., जी.एन.पी., एन.डी.पी., एन.एन.पी. 44

3.4 आय के प्रकार एवं महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ 46

3.5 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 48

4. भारत में आर्थिक नियोजन **52-95**

4.1 नियोजन : अभिप्राय, उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषताएँ एवं प्रकार 52

4.2 योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग 55

4.3 पंचवर्षीय योजनाएँ 75

4.4 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधार 83

4.5 उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण 84

5. समावेशी विकास तथा सामाजिक समावेशन **96-138**

5.1 समावेशी विकास : आशय एवं अवधारणा 96

5.2 सामाजिक समावेशन 100

5.3 गरीबी 101

5.4 बेरोज़गारी 116

5.5 क्षेत्रीय असंतुलन : कारण एवं समाधान 126

5.6 प्रव्रजन : कारण एवं समाधान 128

5.7 सतत् विकास 130

6.	**कृषि**	**139-218**
6.1	आर्थिक विकास में कृषि का योगदान	139
6.2	फसल एवं उसके प्रकार	150
6.3	बीज : प्रजनक बीज, फाउंडेशन बीज, प्रमाणित बीज एवं जी.एम. बीज	155
6.4	जैविक उर्वरक एवं रासायनिक उर्वरक	157
6.5	भूमि सुधार प्रणाली	158
6.6	कृषि विपणन	166
6.7	हरित क्रांति : विशेषताएँ, प्रभाव तथा द्वितीय हरित क्रांति	169
6.8	सिंचाई	173
6.9	कृषि साख	174
6.10	खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक	176
6.11	सार्वजनिक वितरण प्रणाली : उद्देश्य एवं सीमाएँ	183
6.12	सब्सिडी : खाद्य सब्सिडी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी	187
6.13	कृषि से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक	189
6.14	कृषि से संबंधित योजनाएँ	196
6.15	मध्य प्रदेश में कृषि की महत्ता	201
6.16	खाद्य प्रसंस्करण	203
7.	**औद्योगीकरण**	**219-256**
7.1	औद्योगीकरण : आशय एवं उत्पादन के क्षेत्र	219
7.2	भारतीय औद्योगिक नीति	220
7.3	निवेश एवं विनिवेश	224
7.4	औद्योगिक रुग्णता	230
7.5	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग	232
7.6	भारत में सार्वजनिक उद्यम : महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न	233
7.7	औद्योगिक वित्त के स्रोत	236
7.8	भारत में उद्योग	237
7.9	औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएँ एवं कार्यक्रम	244
7.10	आधारभूत अधोसंरचना	250
7.11	मध्य प्रदेश का औद्योगीकरण	251
8.	**बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली**	**257-319**
8.1	मुद्रा और बैंकिंग	257
8.2	परिसंपत्तियाँ एवं देयता सृजन	276
8.3	भारतीय रिज़र्व बैंक	281
8.4	वित्तीय समावेशन	289
8.5	शेयर बाज़ार, प्रतिभूति बाज़ार एवं सेबी	303
8.6	भारत में म्यूचुअल फंड एवं बीमा क्षेत्र	308
8.7	डिपॉजिटरी प्रणाली, कमोडिटी एक्सचेंज एवं डेरिवेटिव्स	309
8.8	मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति	311

अध्याय
1

भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय (Indian Economy : General Introduction)

प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। मध्यकाल में भारत का व्यापार अरब देशों, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों तथा यूरोपीय देशों तक फैला हुआ था, लेकिन 18वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, फलतः वह दयनीय स्थिति में आ गई लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में गति प्रदान करने तथा विकास की निरंतरता को बनाए रखने हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1991 में नई आर्थिक प्रणाली लागू कर उदारीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा दिया गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर बढ़ाई जा सके।

1.1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था *(Economics and Economy)*

अर्थशास्त्र *(Economics)*

अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा मानी जाती है जिसमें हम उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। **एडम स्मिथ** को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र की अवधारणा में बैंकिंग, राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि को भी शामिल किया जाता है।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economics)

अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)

- व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे- एक व्यक्तिगत फर्म या उत्पादन गृह अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता।
- इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा उस उत्पाद की कीमत का निर्धारण किया जाता है।

समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

- समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।
- इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर को निर्धारित किया जाता है।
- रोज़गार, मुद्रा, सामान्य कीमत, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास आदि का अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है।

अर्थव्यवस्था *(Economy)*

किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से, उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए, मुद्रा (Money) को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही **अर्थव्यवस्था** कहलाती है। 'अर्थव्यवस्था' शब्द को किसी देश के साथ जोड़कर प्रायः पूर्ण बनाया जाता है, जैसे- भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था आदि। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली अवधारणा है जिसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं उनके स्तर से होता है। वह क्षेत्र एक गाँव, राज्य या संपूर्ण देश भी हो सकता है।

आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय को शामिल किया जाता है।

उत्पादन (Production) : उत्पादन का अर्थ आगतों या कारकों को उत्पाद में बदलना है।

उपभोग (Consumption) : अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही उपभोग कहलाता है।

14.	वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 2019	कनाडाई थिंक टैंक फ्रेज़र इंस्टिट्यूट और भारतीय थिंक टैंक 'सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी' द्वारा संयुक्त रूप से	हॉन्गकॉन्ग	79	162	● यह दुनिया के देशों में सरकार के कानून व्यवस्था व सपंत्ति का अधिकार, आकार, मुद्रा की सुगमता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आज़ादी और नियमन जैसे पाँच क्षेत्रों के एकत्र किये गए आँकड़ों के आधार पर जारी किया जाता है। ● इस सूचकांक में वेनेजुएला सबसे निम्न स्थान (162वाँ) पर है।

नोट:

*[1] : बेलारूस (सहित अन्य 16 देशों में बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, कोस्टारिका, क्रोएशिया, क्यूबा, एस्टोनिया, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य, तुर्की, यूक्रेन, उरुग्वे शामिल हैं।)

*[2] : इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में बहुआयामी रूप में गरीब लोगों की संख्या एवं प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जबकि मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था है।
- भारत एक विकासशील देश है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है।
- बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आयात एवं निर्यात बिल्कुल संभव नहीं है।
- खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना प्रतिबंध के वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है।
- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है।
- व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को **ट्रेड मॉर्क** कहा जाता है।
- निर्माण एवं विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- श्रम, भूमि, पूंजी एवं उद्यमशीलता उत्पादन के कारक हैं।
- सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वर्ष 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' थी।
- बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं।
- भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ श्रम आधिक्य की स्थिति रहती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. एक 'बंद अर्थव्यवस्था' वह अर्थव्यवस्था है, जिसमें- **M.P.P.C.S. (Pre) 2017**
   (a) मुद्रा-पूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित है
   (b) घाटा वित्तीयन होता है
   (c) केवल निर्यात होते हैं
   (d) न निर्यात और न ही आयात होते हैं

2. मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है- **M.P.P.C.S. (Pre) 2016**
   (a) कृषि-प्रधान (b) पूंजी-प्रधान
   (c) उद्योग-प्रधान (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है?

M.P.P.C.S. (Pre) 2008

(a) प्राथमिक क्षेत्र
(b) द्वितीयक क्षेत्र
(c) तृतीयक क्षेत्र
(d) सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं

4. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है?

(a) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
(b) समाजवादी अर्थव्यवस्था
(c) मिश्रित अर्थव्यवस्था
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है-

(I) कृषि की प्रधानता
(II) उद्योग की प्रधानता
(III) न्यून प्रति व्यक्ति आय
(IV) वृहद् बेरोज़गारी

नीचे लिखे कूट से सही उत्तर चुनिये-

(a) I व II केवल (b) I, II व III केवल
(c) II, III व IV केवल (d) I, III व IV केवल

6. निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है?

(a) श्रम (b) भूमि
(c) पूंजी (d) उपभोग

7. निम्नलिखित में कौन-सा तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है?

(a) परिवहन (b) खनन
(c) बैंकिंग (d) बीमा

8. भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी-

(a) 1909 में (b) 1907 में
(c) 1905 में (d) 1911 में

9. औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में कौन-से घटक शामिल थे?

(a) स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा प्रसार, विनिर्माण
(b) रेल, पत्तन, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र
(c) रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक व तार
(d) सेवा क्षेत्र, डाक व तार

10. निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है?

(a) श्रम की न्यून कार्यक्षमता
(b) प्रति व्यक्ति कम आय
(c) पूंजी निर्माण की न्यून दर
(d) प्राकृतिक संसाधनों की कमी

11. देश की आर्थिक वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन-सा अनार्थिक तत्त्व है?

(a) सामाजिक व्यवहार (b) प्राकृतिक संसाधन
(c) शक्ति संसाधन (d) पूंजी संसाधन

उत्तरमाला

1. (d) 2. (a) 3. (c) 4. (c) 5. (d) 6. (d) 7. (b) 8. (b) 9. (c) 10. (d) 11. (a)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 10-20 शब्दों/एक या दो पंक्तियों में दीजिये)

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था **M.P.P.C.S. (Mains) 2016**
2. मिश्रित अर्थव्यवस्था **M.P.P.C.S. (Mains) 2015**
3. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर 50 शब्दों या 5 से 6 पंक्तियों में दीजिये)

1. उत्पादन के कारक
2. बंद अर्थव्यवस्था
3. द्वितीयक क्षेत्र
4. उपभोग

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/200/300 शब्दों में दीजिये)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। **(300 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2018**
2. भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों समझा जाता है? विश्लेषण कीजिये। **(100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2018**
3. भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। **(300 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2017**
4. भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों की व्याख्या कीजिये। **(100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2017**
5. भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। इस संबंध में अपने सुझावों को भी बताइये। **(300 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2015**
6. अविकसित राष्ट्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिये। **(100 शब्द) M.P.P.C.S. (Mains) 2015**
7. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना कीजिये।
8. स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
9. भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करें।
10. स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन-से बदलाव हुए? चर्चा कीजिये।

अध्याय
2

आर्थिक विकास, आर्थिक संवृद्धि एवं अल्प विकास
(Economic Development, Economic Growth and Under Development)

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। सतत् गतिशीलता एवं अनिवार्य आवश्यकता के रूप में आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक चिंतन का केंद्र-बिंदु माना जाता है। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन किया जाता है। आर्थिक संवृद्धि एवं विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया से जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसलिये आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि का प्रश्न विकसित, विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के लिये समान रूप से महत्त्व रखता है। एक ओर अल्प विकसित देशों एवं विकासशील देशों के लिये निर्धनता, बेरोज़गारी, उत्पादन क्षमता में सुधार एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिये विकास की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण है, तो दूसरी ओर विकसित देशों के लिये आर्थिक विकास का महत्त्व इसे निरंतर रूप से बनाए रखने में निहित है।

2.1 आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि
(Economic Development and Economic Growth)

आर्थिक विकास *(Economic development)*

आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास में गैर-आर्थिक चर को भी शामिल किया जाता है, जैसे- शिक्षा एवं साक्षरता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएँ, जीवन प्रत्याशा तथा लैंगिक विकास आदि।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, "विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है, आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है, जिससे राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।''

आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योगों, विनिर्माण, सेवा एवं बैंकिंग आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा सर्वाधिक होता है।

अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया था, जबकि महबूब-उल-हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था।

अत: आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधन; जैसे- पूंजी, श्रम, तकनीक आदि एक-दूसरे पर ऐसा अनुकूल प्रभाव डालते हैं जिससे आय वृद्धि के कारण क्रय शक्ति भी बढ़ती है।

आर्थिक संवृद्धि *(Economic growth)*

आर्थिक संवृद्धि को प्राय: सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि के रूप में समझा जाता है। सामान्यत: आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है जो कि श्रमशक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार के विस्तार के साथ होता है। आर्थिक संवृद्धि होने पर आर्थिक विकास हो, यह आवश्यक नहीं है, किंतु आर्थिक विकास होने पर निश्चित रूप से आर्थिक संवृद्धि होती है।

वर्ष 1970 से 1980 के बीच आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि को एक ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक संवृद्धि को आर्थिक विकास का एक भाग माना जाता है। आर्थिक संवृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है।

अध्याय
3

राष्ट्रीय आय
(National Income)

राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है, जो नीति-निर्माण एवं कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्रियाओं की माप होती है। राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने व प्राथमिकताओं को स्थापित करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण सूचकांक है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिये वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे।

3.1 राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा *(Meaning and Concept of National Income)*

राष्ट्रीय आय का अर्थः राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पादित अंतिम 'वस्तुओं एवं सेवाओं' के मौद्रिक मूल्य से होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक लेखा वर्ष की अवधि के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाज़ार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में देश के निवासियों द्वारा घरेलू एवं विदेशों से अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है–

मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय (National income according to Marshal)

- राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर होती है।
- वार्षिक कुल उत्पादन में से मशीनों की टूट-फूट, घिसावट और उत्पादन संबंधी व्यय आदि को घटा दिया जाता है।
- राष्ट्रीय आय में विदेशी विनियोगों से प्राप्त होने वाली राशि को जोड़ दिया जाता है।
- व्यक्तियों की वे सेवाएँ, जो परिवार के सदस्यों एवं मित्रों को बिना मूल्य प्राप्त हो जाती हैं।
- निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त लाभ इत्यादि को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिये।

पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय (National income according to Pigou)

- राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय होती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है, यह वह भाग होती है, जिसको द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है।

फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय (National income according to Fishar)

- राष्ट्रीय आय में केवल उन सेवाओं को शामिल किया जाता है, जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को उपभोग के लिये प्राप्त होती हैं, फिर चाहे वे भौतिक वातावरण से प्राप्त हों अथवा मानवीय वातावरण से।

राष्ट्रीय आय की अवधारणा *(Concept of national income)*

- राष्ट्रीय आय में किसी एक समय पर उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक को नहीं, बल्कि किसी समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है।
- राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की **बाज़ार कीमत** पर गणना की जाती है और एक वस्तु की कीमत एक बार ही शामिल की जाती है, इसलिये अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है, ताकि दोहराव से बचा जा सके।

अध्याय
4

भारत में आर्थिक नियोजन
(Economic Planning in India)

आर्थिक नियोजन (आयोजन) योजनाबद्ध तरीके से किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। आर्थिक नियोजन में सामाजिक नियोजन की अवधारणा स्वत: ही सम्मिलित रहती है। भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में नियोजन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। आर्थिक नियोजन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं उन्नति के लिये स्वीकार किया गया है।

भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्रतर बनाना नीतिगत कार्यों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ विकास के लिये अनुकूल परिवेश तैयार करना तथा लक्षित कार्यों को नियोजित तरीके से पूर्ण करने के लिये नियोजन अनिवार्य है।

4.1 नियोजन : अभिप्राय, उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषताएँ एवं प्रकार *(Planning : Significance, Objective, Requirement, Features and Type)*

नियोजन का अभिप्राय *(Significance of planning)*

राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, साथ ही सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रण तथा समन्वय किया जा सके, अवधारणा **नियोजन** कहलाता है।

नियोजन के उद्देश्य *(Objective of planning)*

- संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना।
- निर्धनता को समाप्त करना।
- बेरोज़गारी दूर करना।
- आधारभूत संरचना का विकास करना।
- कृषि एवं उद्योग का विकास सुनिश्चित करना।
- सामाजिक न्याय के साथ ही साथ विकास की गति को तीव्र करना।

नियोजन की आवश्यकता *(Requirement of planning)*

- गरीबी, बेरोज़गारी कम करने के लिये।
- निम्न उपभोग स्तर को बढ़ाने के लिये।
- गरिमाहीन जीवन शैली के उन्नयन हेतु।
- उद्योग का अभाव, व्यापार के अभाव को कम करने के लिये।
- कौशल के अभाव तथा वित्तीय संसाधनों के अभाव को कम करने के लिये।

नियोजन की विशेषताएँ *(Features of planning)*

- भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वभाव निदेशात्मक है।
- आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने में प्रोत्साहन को वरीयता दी जाती है।
- आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत है (सामान्यत: राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों को छोड़कर)।

अध्याय
5

समावेशी विकास तथा सामाजिक समावेशन (Inclusive Growth and Social Inclusion)

प्रत्येक व्यक्ति समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। भारतीय समाज में कई ऐसे वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत हैं, जैसे- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतू जातियाँ, महिलाएँ, गरीब, किन्नर एवं शरण ार्थी। इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन एक-दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जहाँ **समावेशी विकास** अंतिम व्यक्ति तक विकास के वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है, वहीं **सामाजिक समावेशन** समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्त्व दिये जाने की वकालत करता है, जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। समावेशी विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन, समावेशी विकास का प्रमुख आधार है। समाज में सामाजिक अपवंचन से मुक्ति समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन के द्वारा ही संभव है।

5.1 समावेशी विकास : आशय एवं अवधारणा *(Inclusive Growth : Meaning and Concept)*

समावेशी विकास से आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह जाए, अर्थात् समान अवसरों के साथ-साथ विकास करना ही समावेशी विकास है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का व्यापक रूप से उपयोग किया। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु प्रभावी तथा संपोषणीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिये **बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)** की अवधारणा का केंद्र–बिंदु **तीव्र, धारण ीय और अधिक समावेशी विकास** रखा गया।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा व्यक्तियों द्वारा जीवन–यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है। गरीब एवं हाशिये पर रह रहे लोगों के विकास पर बल, बेहतर रहन–सहन के वातावरण, अवसरों का अधिकतम समान वितरण करने की आवश्यकता है। महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके सशक्तीकरण पर बल देते हुए उनकी शिक्षा एवं रोज़गार की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और वित्तीय समस्याओं तथा अपवर्जन से जूझ रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था करती है। समावेशी विकास में आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है।

समावेशी विकास स्थापित करने के महत्त्वपूर्ण घटक *(Important components to establish inclusive growth)*

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेरोज़गारों के सामान्य एवं कमज़ोर वर्ग के लिये विशेष उपबंध करना। रोज़गार में वृद्धि को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना।
- आधारभूत आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना ताकि इस क्षेत्र में निवेश वृद्धि एवं आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

अध्याय
6

कृषि
(Agriculture)

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। स्वतंत्रता से पूर्व आय के साधन के रूप में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान लगभग 16% है जबकि वर्ष 1950–51 में यह हिस्सा लगभग 51% था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो कृषि की भागीदारी उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की तुलना में कम है। खाद्यान्न उत्पादन जहाँ 1951–52 में मात्र 52 मिलियन टन था वहीं 2016–17 में यह बढ़कर 275.7 मिलियन टन हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर 4.72% थी वही नौवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर क्रमश: 2.5%, 2.4%, 3.2% रही थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर का लक्ष्य 4% रखा गया है।

6.1 आर्थिक विकास में कृषि का योगदान
(Contribution of Agriculture in Economic Development)

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950–51 में यह लगभग 51 प्रतिशत था। देश में मौजूदा बाज़ार कीमतों पर सकल संवर्द्धित मूल्य (Gross Value Added) में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5 प्रतिशत हो गया है। देश के कुल जीवीए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा गैर-कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्राप्ति के कारण गिर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य संवर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 275.11 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़कर 281.4 मिलियन टन हो गया है। अत: वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

रोज़गार

भारत में कृषि रोज़गार का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में आज भी लगभग 50 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व

कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों, जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों, चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान

कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करता है। ये सभी कृषि वस्तुएँ भारत के कुल निर्यातों का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती हैं।

गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आधी से अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि आज भी निम्न आय वर्ग एवं निर्धन व्यक्तियों का जीवन आधार है। कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा का मुख्य अस्त्र है।

अध्याय 7

औद्योगीकरण (Industrialization)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिये औद्योगीकरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। औद्योगीकरण से अर्थव्यवस्था के ढाँचे में व्यापक एवं दीर्घकालीन परिवर्तन आता है। औद्योगीकरण किसी राष्ट्र की प्रगति एवं संपन्नता का आधार ही नहीं, वरन् उसके विकास का मापदंड भी माना जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिये विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों में औद्योगीकरण को अधिक महत्ता दी जाती है।

प्राचीनकाल में भारत शिल्प, वस्त्र, रत्न-आभूषण एवं मसालों आदि के लिये प्रसिद्ध था, परंतु ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय उद्योग पूर्णत: गर्त में चला गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में उद्योगों के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए तीव्र औद्योगीकरण हेतु योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई।

नब्बे के दशक में आर्थिक मंदी का सामना करने के लिये भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों हेतु नई आर्थिक नीति को अपनाया। नई आर्थिक नीति के द्वारा भारत में औद्योगीकरण को नई दिशा एवं दशा मिली है।

7.1 औद्योगीकरण : आशय एवं उत्पादन के क्षेत्र *(Industrialization : Meaning and Sector of Production)*

औद्योगीकरण का आशय राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश के ढाँचे में उद्योगों की बहुलता से है जिससे सकल घरेलू उत्पाद तथा श्रमशक्ति के प्रयोग में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धीरे-धीरे सामान्यतया राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता जाता है तथा औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है।

दूसरे शब्दों में, प्राथमिक उत्पादों के द्वितीयक उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को औद्योगीकरण कहते हैं। यह कार्य विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसके लिये उद्योगों में निवेश अत्यंत आवश्यक है। औद्योगीकरण द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में, उद्योगों के उत्पादन में बहुलता एवं सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाया जाता है।

उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उत्पादन क्रियाओं को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है-

- **प्राथमिक क्षेत्र (Primary sector) :** नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें प्राथमिक वस्तुएँ कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
- **द्वितीयक क्षेत्र (Secondary sector) :** प्राथमिक वस्तुओं में एक या कई बार मूल्यवर्द्धन द्वारा जिन नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन्हें द्वितीयक वस्तुएँ कहा जाता है तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं।
- **तृतीयक क्षेत्र (Tertiary sector) :** अदृश्य सेवाओं को तृतीयक वस्तुएँ कहते हैं तथा सेवाओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (C.S.O.) द्वारा उत्पादन क्षेत्रों का किया गया वर्गीकरण निम्नलिखित है-

उत्पादन क्षेत्र

- **प्राथमिक क्षेत्र**
  - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
  - वानिकी एवं लट्ठ उत्पादन
  - मत्स्यपालन
  - खनन एवं उत्खनन
- **द्वितीयक क्षेत्र**
  - विनिर्माण
  - निर्माण
  - जलविद्युत एवं गैस आपूर्ति
- **तृतीयक क्षेत्र**
  - होटल, रेस्तराँ एवं व्यापार
  - परिवहन, संचार एवं भंडारण
  - बैंकिंग एवं बीमा
  - वास्तविक संपदा तथा वाणिज्यिक आवासों एवं सेवाओं का स्वामित्व
  - लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा
  - अन्य सेवाएँ

अध्याय
8

बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली (Banking and Financial System)

बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता की धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकतानुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। आर्थिक नियोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिये बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। दूसरी ओर, वित्तीय प्रणाली से आशय बाज़ार की संस्थाओं से है जो कि अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की ओर गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

8.1 मुद्रा और बैंकिंग *(Money and Banking)*

मुद्रा *(Money)*

मुद्रा वह केंद्र है जिसके चारों ओर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की चक्रीय गति होती है। आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य 'वस्तुओं तथा सेवाओं के लेन-देन को सरल बनाना है'। इसमें बैंकों की विशेष भूमिका होती है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार, "मुद्रा ऐसी कोई भी संपत्ति है जिसमें क्रयशक्ति के अस्थायी निवास के रूप में कार्य करने की क्षमता हो।" दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि "मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है।"

मुद्रा की उत्पत्ति विनिमय के माध्यम के रूप में हुई है। अत: कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों (जिसमें ऋण भी सम्मिलित है) को पूरा करने में भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं।

मुद्रा के प्रकार (Type of money)

मुद्रा के दो प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं–

- **वैधानिक मुद्रा (Legal currency) :** वह मुद्रा जिसका निर्गमन सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया है। वैधानिक मुद्रा में रिज़र्व बैंक धारक को उतनी रकम अदा करने का वचन देता है, जितने मूल्य की करेंसी है।
- **साख मुद्रा (Credit money) :** वह मुद्रा जिसका भुगतान चेक या अन्य माध्यमों से किया जाता है। यह एक ऐच्छिक मुद्रा है, जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं है। सामान्यत: साख मुद्रा के 5 रूप प्रचलित हैं-
  - प्रतिज्ञा-पत्र (Bond)
  - चेक (Cheque)
  - हुंडी (Hundi)
  - विनिमय-पत्र (Exchange Deed)
  - बैंक-ड्राफ्ट (Bank Draft)

सांकेतिक मुद्रा (Token money)

यह वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। यह सस्ती धातु से बनी होती है। उदाहरण- भारतीय सिक्के।

प्रामाणिक मुद्रा (Standard money)

यदि सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे 'प्रामाणिक मुद्रा' कहते हैं। सोने और चांदी के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा ही होते हैं।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596